1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th April, 1970, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12·19 Hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 11th May, 1970, will consist of :—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from to-days' Order Paper.

(2) Consideration and passing of the University Grants Commission (Amendment) Bill, 1968, as passed by Rajya Sabha and discussion on the Report of the Universsity garnts Commission for 1965-66, 1966-67 and 1967-68 on a motion to be moved by the Minister of Education and Youth Services.

(3) Discussion on the Report (Part I) of Committee of Enquiry (Council of Scientific and Industrial Research) on a motion to be moved by the Minister of Education and Youth Services.

(4) Consideration and passing of the Patents Bill, 1967, as reported by the Joint Committee.

(5) Consideration of a Motion for modification of Foreign Exchange Regulation (Publication of Name) Rules, 1970 by Shri Srinibas Mishra at 5 p.m. on Monday, the 11th May, 1970.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : On the 11th, Shri Srinibas Mishra will not be here.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुवनी) : अध्यक्ष महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना पर बहस होगी, और उस के लिये तीन घंटे भी निर्धारित कर दिये गये थे। लेकिन बुलेटिन में इस का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर बहस होगी कि नहीं ? क्योंकि सेशन समाप्त होने में अब बहुत कम समय रह गया है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं। सरकार के द्वारा जिस कार्यक्रम की घोषणा की गयी है, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जो स्पैशल मैरिजेज़ बिल है, जिस के बारे में आप को भी मैंने लिखा था, प्रधान मंत्री जी को भी लिखा था और प्रधान मंत्री जी ने मुझे लिखित आश्वासन दिया था कि यह बात सही है कि पार्लियामेंट जितना ध्यान उसे सामाजिक कानूनों की ओर देना चाहिए वह नहीं दे रही है। उन्होंने कहा था कि उस कार्य को इस बजट सत्र में प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन यह बजट सत्र खत्म होने जा रहा है। आप ने अगले सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा की है लेकिन उस में स्पैशल मैरिज बिल का कोई जिक्र नहीं है।

दूसरी बात यह है कि दिन प्रतिदिन विधान सभाओं के सत्रों के बीच में अन्तर बढ़ता जा रहा है। उन की बैठकों के दिन कम होते चले जा रहे हैं और जो निर्धारित तिथि है उस के पहले ही उन को ऐडजोर्न कर दिया जाता है। केरल में भी किया गया और गुजरात में भी किया गया। इस के बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया था तो उस को चर्चा के लिए क्यों नहीं लिया जा रहा है ? यह सारे मामलात अदालत में जा रहे हैं। अच्छा तो यह होगा कि हमारी यह राष्ट्रीय पंचायत है हमें इस के ऊपर बहस करने का मौका दिया जाय। इसलिए सरकार मेरे इस प्रस्ताव पर विचार के लिए भी कुछ समय इसी बजट सत्र के दौरान निकाल ले।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I want to raise three small points.

We want a discussion next week because Parliament is coming to an end.

AN HON. MEMBER : How is Parliament coming to an end ?

SHRI S. M. BANERJEE : Because the session is coming to an end.

MR. SPEAKER : Unwittingly he has said that.

SHRI S. M. BANERJEE : We would like to have a discussion on Combodia, because most dangerous and mischievous statements have been made by the American Vice-President regarding India. I know you have kindly admitted the Calling Attention on Monday. But we want a full scale discussion on Cambodia.

My second points is this. You are aware that in this House the Minister for Defence Production and the Defence Minister made a definite declaration that no employee in the ordinance factory will be declared surplus or retrenched. Today, we have received telegrams—Mr. Joshi and myself—and a letters also we have got....

MR. SPEAKER : Don't take opportunity from this simple item to go into that.

SHRI S. M. BANERJEE : Kindly hear me, Sir. On this point I only request the hon. Minister to convey our feelings to the Defence Minister and request him to make a statement. Otherwise the situation will be dangerous.

My third point is this. We should have some discussion on the communal disturbance. Even yesterday and in today's papers the incidents in Bhimri in Maharashtra have been reported and a minority community has been butchered. I would request him to kindly allow a statement to be made by the hon. Minister and after that we may have a full-scale discussion on the communal disturbances.

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, एक तो कम्बोडिया के बारे में डिस्कशन के लिए सुझाव दिया गया है मैं भी प्रस्ताव करूंगा कि इस सैशन के दौरान एक डिबेट ईस्ट ऐशिया के बारे में करने के लिए समय निकालना चाहिए ।

दूसरे दिल्ली का ला एंड आर्डर सेंटर के पास है और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातों में सेंटर का अधिकार है । लेकिन इस सारे सैशन के अन्दर दिल्ली के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हुई । मेरा आप से आग्रह है कि दो, तीन घंटे निकाले जायं जिससे दिल्ली की समस्याओं की, विशेष रूप से यहां के ला एंड आर्डर के बारे में, यहां के स्लम्स और अनऐथोराइज्ड कालोनीज़ के बारे में और अन्य समस्याएं जिनका सम्बन्ध केन्द्र के साथ है उन सब पर विचार किया जाय ।

तीसरी चीज़ मैं चाहूंगा कि यह कम्यूनलिज्म के बारे में जो चर्चा है सब लोग बोलते हैं communalism, communalism. What is communalism ?

इस के बारे में इस सदन में चर्चा हो ताकि हम साबित कर सकें कि उधर की बेंचों पर बैठे हुए वह सब लोग कम्युनल हैं और जानबूझ कर कम्युनलिज्म को फैलाते हैं ।

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad) : I am all for Combodia, communalism and all other issues concerning the whole world. But, Sir, for Telangana, we have been agitating day in and day out. The other day they promised that they will give three hours. Now, this week is over and in the next week some other excuse will come and this session will be over, Sir. So my only request is that some time should be found for this discussion on Telangana in the coming week.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Sir, the census work is going to be started and before the census work is taken up in hand—and I think the whole House will agree—the scheduling and re-scheduling to the Bill as a reported by the Joint Committee should be completed during this session.

Otherwise, the work will be held up and one-fifth of the population of this country will suffer. Therefore, it ought to be taken up. And some time must be found for that. We can have an extra sitting if necessary. But, before the census work is started, this work must be completed.

श्री इसहाक सम्भली (आरोहा) : स्पीकर साहब, आप ने आज के अखबार में पढ़ा होगा और इस से पहले भी यह आ चुका है कि हिन्दुस्तान में कई जगह बहुत से सीरियस कम्युनल डिस्टरबैंसेज हो रहे हैं । भीवाड़ी महाराष्ट्र

[श्री इसहाक सम्भाली]

के बारे में आज आप ने पढ़ा होगा कि वहां कितने सिरियस डिस्टरबैंसेज़ हुए हैं। रात भर भीमड़ी जलती रही है। सुबह मेरे पास टेलीफोन आया है। भीमड़ी में माइनारिटीज़ के मकान और दुकानें जलती रही हैं और तबाह होती रही हैं। फ़ायर ब्रिगेड ने भी वहां जाने से इंकार कर दिया। भीमड़ी और चाइबासा के बारे में यहां पर इसी सैशन के दौरान डिस्कशन होना चाहिए।

अजीब बात है कि उन्हीं के मकान जलाये जाते हैं, उन्हीं के मकान लूटे जाते हैं, वही कत्ल किये जाते हैं। लेकिन वही पकड़े जाते हैं और पुलिस के जरिए उन्हीं बेचारों पर ज्यादतियां की जा रही हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसी सैशन के दौरान अगले सप्ताह इस मसले पर ज़रूर डिस्कशन हो जाना चाहिए।

[شری اسحاق سمبھلی (امروھه) : اسپیکر صاحب - آپ نے آج کے اخبار میں پڑھا ھوگا اور اس سے پہلے بھی یه آچکا ھے که ھندوستان میں کئی جگہه بہت سے سیریس کمیونل ڈسٹربنسیز ھو رھے ھیں - بھیمڑی مہاراشٹر کے بارے میں آج آپ نے پڑھا ھوگا که وھاں کتنے سیریس ڈسٹربنسز ھوے ھیں - رات بھر بھیمڑی جلتی رھی ھے - صبح میرے پاس ٹیلیفون آیا ھے - بھیمڑی میں مائنارٹیز کے مکان اور دکانیں جلتی رھی ھیں اور تباہ ھرتی رھی ھیں - فائر بر گیڈ نے بھی وھاں جانے سے انکار کر دیا - بھیمڑی اور چائی‌باسا کے بارے میں یہاں پر اسی سیشن کے دوران ڈسکشن ھونا چاھئے -

عجیب بات ھے که انہیں کے مکان جلائے جاتے ھیں - انہی کے مکان لوٹے جاتے ھیں - وھی قتل کئیے جاتے ھیں لیکن وھی پکڑے جاتے ھیں اور پولیس کے ذریعه انہیں بیچاروں پر زیادتیاں کی جا رھی ھیں - اسلئے میں چاھونگا که اسی سیشن کے دوران اگلے سپتاہ اس مسلئے پر ضرور ڈیسکشن ھو جانا چاھیئے -]

श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, पहले हम लोगों को यह इनफोरमेशन दी गई थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर इसी सैशन के दौरान बहस होगी।

उस के लिए समय भी निर्धारित किया गया था जोकि करीब तीन घंटे का था। लेकिन अभी जो ऐलान मंत्री महोदय ने किया है उस में जहां तक मैं सुन सका हूं इस चौथी पंचवर्षीय योजना पर डिस्कशन के मुताल्लिक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। आगामी सप्ताह के बाद सैशन खत्म होने में दो, तीन दिन ही और रह जाते हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर इस चौथी पंचवर्षीय योजना पर बहस कब हो सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर इसी सैशन में हम लोगों को बहस करने का मौक़ा मिलेगा या नहीं? सरकार इस पर इसी सैशन के दौरान डिस्कशन कराना चाहती है या नहीं या सरकार सारे हाउस को अंधेरे में रखना चाहती है इस का जबाव मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं?

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : The people of India have been terribly shocked by the report of barbarous mass execution after public trial in thousands in China.

I want to know from the Government whether the Government will issue a statement condemning these barbarous, savage, and inhuman acts of the Chinese.

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के चलते मधु लिमये जी का आई० सी० एस० लोगों के प्रीविलेज़ज खत्म करने वाला बिल पारित नहीं हो पाया। कल हम लोगों ने आप को चिट्ठी भी लिख कर भेज दी है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के सिलसिले में पार्लियामेंट में इसी सैशन में बहस होनी चाहिए। ख़ास कर आप जानते हैं कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसर सारे प्रशासन पर हावी हो गये हैं। ए० आर० सी० की पर्सनल मैनेजमेंट पर रिपोर्ट आ चुकी है इसलिए मैं आप के जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के सिलसिले में अगले सप्ताह बहस के लिए कुछ समय निर्धारित करना चाहिए।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 4-6 महीनों से हम देख रहे हैं कि हिन्दुओं के धार्मिक जलूसों पर हमले होते हैं। चाइबासा में रामनवमी जलुस पर बमों से हमला हुआ। अब कल शिवाजी जयन्ती पर हमला हुआ है। इस से पहले अहमदाबाद में हमला हुआ था। सारे देश में साम्प्रदायिक तत्वों और देश विरोधी तत्वों की यह एक संगठित योजना दिखाई देती है। यह पहले हमले करते हैं और बाद में उलटे गालियां देते फिरते हैं। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए, खुल कर यहां पर वादविवाद हो ताकि वे लोग जो देशभक्ति के नाम पर साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं उन का दमन हो सके।

श्री सरजू पाण्डेय (गाजी पुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सी० एस० आई० आर० में बहुत गम्भीर मामले पैदा हो गये हैं इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए। ख़ास तौर से लखनऊ बुटैनिकल गार्डन में बहुत ही भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। वहां के साइंटिस्ट्स और अन्य सारे इम्पलायीज़ आन्दोलन करने पर उतारू हो गये हैं यहां पर प्रश्न भी उठाया गया था लेकिन शिक्षा मंत्रालय अथवा प्रधान मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस मामले को बजट सैशन के इसी सत्र में लिया जाय और उस पर डिस्कशन कराया जाय।

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : I think the House should discuss the activities of the Naxalites in the country as also the extension of the activities of Naxalites into Assam. In Tinsukia, Mahatma Gandhi's statue has been desecrated. There are reports that Chinese and Pakistani currency notes have been distributed in that part of the country. This is a strategic area and so I think that the Naxalite activities all over the country should be discussed by a Resolution.

Secondly, on a previous occasion, the Government spokesman told about the discussion on the Report of the Committee on Defections. Firstly I do not find any mention in the Statement made by the hon. Minister. This House should not encourage defection. This is a bad thing and we must condemn it. Therefore, there should be a discussion on that report also. But Government seem to be so careless and so indifferent to that report. I do not understand why.

श्री राम चरण (खुरजा) : मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की जो रिपोर्ट है और पेरूमल कमेटी की जो रिपोर्ट है उस के लिये पांच घंटे रक्खे गये हैं लेकिन सरकार उस को पीछे ही करती जा रही है। मेरा आप से अनुरोध है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के लिये पांच घंटे के बजाय दस घंटे दें और प्रायारिटी दे कर उस पर विचार किया जाय। अगर इस के लिये ओवर-टाइम सिटिंग भी करनी पड़े तो करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मैं इस का समर्थन करता हूं।

SHRI TENNETI VISHWANATHAM (Visakhapatnam) : May I know whether Government are going to make any announcement about the settlement of the Maharashtra-Mysore boundary ? I am interested in it this way; a number of Telugu medical students in Belgaum are being ill-treated by both sections; the Mysoreans mistake them for Maharashtrians and the Maharashtrians mistake them for Mysoreans and they are being beaten up on both sides. Most of the medical students also came and interviewed the Prime Minister yesterday. Will it be possible for Government to make some settlement immediately ? It will give peace not only to Maharashtra and Mysore people but also to the Telugu people there.

SHRI RAGHU RAMAIAH : Most of these matters were considered by the Business Advisory Committee which met on the 5th May. For instance, the report of the committee on defections. the debate on the Plan and various other matters were discussed there. It was found on that day that there were only 32 hours left in this session, so far as Government time was concerned. At the suggestion of the Business Advisory Committee, Government had agreed to allot ten hours out of that time for these various discussions. It is out of that time that we have found time for the debate on prohibition. Most of the subjects have been listed out here, and we shall try to allocate whatever time is possible out of it.

So far as the Special Marriage Bill is concerned, we shall try to find time for it in the last week.

श्री मधु लिमये : ट्राई नहीं, करना ही चाहिये ।

श्री रवि राय : इस को लाइये ।

SHRI RAGHU RAMAIAH : Even to find time, we have to try. Out of defference to Shri Surendranath Dwivedy, I would say, if the House agrees, that I have no objection to postpone the last item relating to modification of foreign exchange regulations to 18th May from 11th May. In accordance with the wishes of the Business Advisory Committee, we shall also try to find time for the Telengana discussion either next week or the week after it, as soon as it is possible.

SHRI BAKAR ALI MIRZA : He should try to find time for it next week.

SHRI S. M. JOSHI (Poona) : It should be taken up during this session.

SHRI SAMAR GUHA : What about the massacre of the Tibetans ?

श्री शिव चन्द्र झा : चौथी पंच-वर्षीय योजना जो इतनी अहम है, उस के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? आप बतलायें कि उस पर बहस होगी या नहीं ।

SHRI A. K. KISKU (Jhargram) : He should find time for discussion on the Scheduled Tribes and Scheduled Castes..

SHRI RAGHU RAMAIAH : The Business Advisory Committee has listed it as one of the subjects, and we shall try to find time for a discussion on the report on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, before the session ends.

SHRI A. K. KISKU : I want to know whether they are coming forward with the Bill....

SHRI HEM BARUA : What has happened to the discussion on the activities of the Naxalites and the report of the committee on defections ?

SHRI ISHAQ SAMBHALI : What about communal disturbances ?

श्री रवि राय : कम से कम सरकार की तरफ से ध्यान होना चाहिये कि माइनारिटीज पर हमला हो रहा है ।

MR. SPEAKER : The hon. Minister may please make a note of all these suggestions and they may be put before the Business Advisory Committee.

SHRI S. M. BANERJEE : We only want a statement on certain items. For instance, on the communal situation, let the hon. Minister make a statement on the matter. Similarly, about the retrenchment in the clothing factories in Kanpur, I want that Government should make a statement.

I do not want any discussion. But we expect that those employees who are rerenched in Kanpur should be given protec-

tion. Do they want a strike for their demands being acceded to? They talk of socialism. But they are handing it over to the private trade. They are retrenching people. It is a shameful commentary on the various assurances of Government.

12·36 Hrs.

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : I beg to move :

> "That the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

This Bill was considered and passed by the Rajya Sabha on 3 December 1969. The amendment Bill seeks to amend the Merchant Shipping Act 1958, for the purpose of giving effect to three International Conventions relating to merchant shipping, namely : (i) the International Convention on Load Lines, 1966; (2) the International Convention relating to the Limitation of liability of owners of sea-going ships, 1957, and (iii) the International Convention for the prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 as amended in 1962.

The position regarding the three conventions is as follows :

The International Convention on Load Lines, 1966, provides for marking of free board, that is, the distance measured vertically downwards from the deckline, which must at all times and under all conditions, while the ship is afloat, remain free of water line. It also provides for marking of load lines indicating how far the ship could be permitted to submerge in water as a result of loading cargo in different seasons and different zones. Attempts have been made from time to time to control the freeboard. The first international agreement on the question was reached by the International Load Line Convention of 1930. Subsequently the 1930 convention was ratified by India in 1934 and it was incorporated in the Merchant Shipping Act of 1923.

The new Load Line Convention tends to liberalise the freeboard requirements as also summer and tropical zones areas so as to permit deeper loading of ships in greater parts of the year as compared to the old convention of 1930. It also ensures better safety of life and property at sea. Accordingly, the ratification of the new Convention was considered to be in the larger interest of Indian shipping. The Convention was thus ratified. The Bill is intended to incorporate the provisions of the 1966 Convention in the Merchant Shipping Act, 1958.

The second is the International Convention for limitation of liability of owners of seagoing ships, 1957. Since the 18th century, legal assistance was being invoked in maritime states against proceedings for damage to property and persons on board. The first convention on the subject was signed in 1924 but it was never ratified by a sufficiently large number of states. It was again amended in 1957. This Bill seeks to adopt the provisions of the Convention.

The third is the International Convention for the prevention of pollution of the Sea by Oil 1954. The Merchant Shipping Act, 1958 does not contain any provision regarding the prevention of the pollution of the sea by oil. The International Convention on the Prevention of the Pollution of the Sea by Oil, 1954, aims at preventing ship-owners from discharging oil and oily mixtures within a radius of 100 miles from the coast. This problem is found in an aggravated form in Europe and some Atlantic areas. It is not very acute in our area, but it is bound to arise with the bringing in of bigger tankers, and therefore India is also concerned. If there is an accident, it is bound to affect a large area as it happened in the Mediterranean two or three years ago. With the adoption of this international convention, our ships going to the countries which have ratified this convention will also be governed by it, and therefore, we are inserting a new provision in the Act.

This is a non-controversial Bill based on international agreements and conventions which have been agreed upon after considering them from all aspects and taking